संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को दफ्तरी भाषा का दर्जा दिया जाना

185. **चौधरी हरमोहन सिंह यादव:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार अभी तक हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र संघ की दफ्तरी भाषा का दर्जा नहीं दिला पायी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है; और

(ग) सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र की दफ्तरी भाषा का दर्जा दिलाने के लिए क्या प्रयास किये है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) से (ग) हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र की एक आधिकारिक भाषा बनाने पर सरकार कई वर्षों से ध्यान देती रही है। संयुक्त राष्ट्र में नई भाषा लागू करने के लिए अत्यधिक वित्तीय व्यय के अतिरिक्त सदस्य राज्यों के बहुमत की भी आवश्यकता होती है। इस संबंध में हमारे परामर्श उत्साहवर्धक नहीं रहे हैं। भारत सरकार अपने प्रतिनिधिमंडल के उन सदस्यों के लिए जो हिंदी में बोलना चाहते हैं, हिंदी अनुवाद, टंकण सुविधाएं मुहैया कराने के लिए न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में अस्थायी प्रबंध करती रही है। हिंदी में दिए जाने वाले भाषणों का मौके पर ही अनुवाद की व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र तथा उसके विशिष्ट अभिकरणों में जब भी आवश्यकता होती है की जा सकती है।

Plea of Indian delegation at U.N. General Assembly Session regarding CTBT and NPT

186. SHRIMATI VEENA VERMA:
SHRI SUSHILKUMAR
SAMBHAJIRAO SHINDE:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Prime Minister and the Indian delegation to the U.N. General Assembly Session held in September this year made a plea for a just and fair world order in the context of CTBT and NPT and the need for Global-Disarmament, if so in what terms; and

(b) what was the response of the U.N. General Assembly and the different world leaders thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SALEEM IQBAL SHERWAI): (a) Yes Sir. Prime Minister, in his address to the 52nd Session of the U.N. General Assembly, stated, inter alia, "The pretexts for clinging to nuclear arsenals, which were questionable at any time, have now vanished. Mere non-proliferation treaties, promoted as disarmament measures serve to entrench a nuclear monopoly...Global opinion wants a Nuclear Weapons Convention, as already outlined for the class of biological and chemical weapons, and will not rest till it is achieved. We appeal to nuclear weapon states to align their policies to what the world wants".

(b) The majority of leaders of the Non-Aligned countries are supportive of India's position. India's stand reflects the common position of the NAM countries on the issue of complete nuclear disarmament as a necessary step towards the establishment of a new, just and non-violent world order. However, consensus on this approach has not been possible due to the position of the nuclear-weapon-states.

सुरक्षा परिषद् में भारत की सदस्यता का समर्थन करने वाले देश

187. **श्री अजीत जोगी:**
श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद् में भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष में है; और

(ख) क्या अमरीका और चीन भी सुरक्षा परिषद् में भारत को शामिल किये जाने की बात का समर्थन कर रहे है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों में से विभिन्न विचारधाराओं वाले अनेक देशों ने भारत की उम्मीदवारी का द्विपक्षीय रूप में अथवा संयुक्त राष्ट्र में समर्थन किया है।

(ख) अमरीका ने किसी देश का नाम लिये बिना यह स्वीकार किया है कि विकासशील देशों को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्यों के रूप में शामिल किया जा सकता है। अमरीका ने यह भी कहा है कि वह स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी का

विरोध नहीं करता। चीन ने भी यह सुझाव दिया है कि विस्तृत सुरक्षा परिषद् में स्थायी सदस्य के रूप में विकासशील देशों को शामिल किया जाना चाहिए।

शातिर अपराधियों को पासपोर्ट जारी किया जाना

188. **श्री रामगोपाल यादव:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि शातिर अपराधियों और बंगलादेशी राष्ट्रिकों को पासपोर्ट जारी करने का सिलसिला बदस्तूर जारी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि बहुत से ऐसे व्यक्तियों को पासपोर्ट जारी किये गये जो बलात्कार, अपहरण, चोरी, सेंधमारी और लूटमार की गिरोहबद्ध वारदातों के अलावा हत्या जैसे संगीन अपराधों में संलिप्त थे;

(ग) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है और वे पासपोर्ट प्राप्त करने में कैसे सफल हो जाते हैं; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री: (श्री सलीम इकबाल शेरवानी):

(क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) पासपोर्ट पुलिस/सी आई डी की निर्दोष रिपोर्ट, जिसमें आवेदक की राष्ट्रीयता भी निर्धारित होती है, प्राप्त होने पर जारी किए जाते हैं। तथापि, यदि पासपोर्ट कार्यालय को पुष्टि के लिए व्यक्तिगत विवरण प्रपत्र भेजने के 4 सप्ताह के भीतर पुलिस/सी आई डी रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो पासपोर्ट बिना पुलिस रिपोर्ट के ही जारी कर दिए जाते हैं। ऐसे मामलों में, यदि पासपोर्ट जारी होने के पश्चात् पुलिस रिपोर्ट प्रतिकूल प्राप्त होती है तो पासपोर्ट अधिनियम 1967 के उपबंधों के अंतर्गत पासपोर्ट जब्त करने/रद्द करने की कार्रवाई, मामले के अनुसार तुरंत की जाती है।

पुलिस रिपोर्ट प्रतिकूल होने के आधार पर रद्द किए गए जब्त किए गए पासपोर्टों के संबंध में आंकड़ें एकत्रित किए जा रहे हैं और सदन के पटल पर रख दिए जायेंगे। इसमें वे मामले भी शमिल होंगे जहां पुलिस व्यक्ति की भारतीय राष्ट्रीयता सिद्ध करने में असमर्थ रही।

Exposure of Pakistan's Terrorist Activities in Jammu and Kashmir

189. SHRI VIRENDRA KATARIA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what positive gains have been achieved during the recent visit of the Prime Minister to America;

(b) whether U.S.A. is taking note of the terrorist activities of Pakistan in Kashmir and inclined to declare Pakistan as a terrorist state; and

(c) what steps Government are taking to expose Pakistan's terrorist activities in Kashmir?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SALEEM IQBAL SHERWANI): (a) This was the first meeting between the two leaders intended to give direction and impetus to Indo-US relations. The meeting was not intended to finalise agreements on specific matters, but to enable a wide ranging exchange of views on bilateral, regional and global issues. As a follow-up to his meeting, number of high level visits have been scheduled by the US including the Secretary of State, Commerce Secretary and Secretary, Health and Human Services etc. During these visits, the dialogue will be taken further and in the course of which, specific issues in areas like economic and commercial cooperation, cooperation in science and technology, health etc., will be taken up.

(b) and (c) Pakistan's continued support to terrorism in J&K and other parts of India have been taken up on several occasions with the US and our concerns will continue to be reiterated. The US Government has recently declared Pakistan based organisation Harkat-ul-Ansar as terrorist organisation under the US laws. Government of India has recently declared Pakistan based organisation Harkat-ul-Ansar as terrorist organisation under the US laws. Government of India has stated that this is a welcome recognition of ground realities. The statement hoped that this latest decision would be followed by a recognition of other similar terrorist groups' and by effective steps to persuade Pakistan to disband the offices, training camps and cadres of the Harkat-ul-Ansar and other terrorist organisations based in Pakistan.